Title: Regarding irregularities in the supply of coal to small scale industries by NCCF.

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लघु उद्योगों को कोयले की उपलब्धता पर की जा रही व्यापक गड़बड़ी का मामला सदन में उठाने की अनुमति चाहता हूं।

विगत आठ माह पहले भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने दिल्ली की एक कम्पनी एन.सी.सी.एफ. को कोल इंडिया की सभी कोयला उत्पादन करने वाली कम्पनियों से प्रति माह 40-40 हजार टन कोयला देश के उन लघु उद्योगों को, जिनकी खपत 500 टन से कम है, को प्रदाय करने हेतु अधिकृत किया गया था, जबकि एन.सी.सी.एफ. देश के किसी भी लघु उद्योग को कोयला उपलब्ध नहीं करा रही है और पूरा कोयला ब्लैक किया जा रहा है। इतना ही नहीं सरकार को उक्त कम्पनी बिक्री कर, आयकर तथा सर्विस टैक्स की करोड़ों रुपये की चोरी कर भारी नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। जिस लोक सभा क्षेत्र से मैं आता हूं वहां सैकड़ों की संख्या में लघु उद्योग हैं, चूना बनाने वाले भट्ठे हैं। आज कोयला न मिलने के कारण वे सब बंद हो रहे हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि पूरे मामले की जांच की जाए तथा कोल इंडिया अपना अनुबंध तत्काल रद्द कर कोयले की कालाबाजारी पर रोक लगाये तथा देश के अंदर कहां-कहां निजी व्यक्तियों को कोयला खदानें उत्खनन हेतु दी गई हैं तथा उनके लिए बिक्री करने की क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं, इस पर मैं आपके माध्यम से सरकार से जानकारी चाहता हूं। धन्यवाद।